

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक, 11 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट में गंगास नदी पर प्रस्तावित बैराज के निर्माण हेतु डी0पी0आर आदि कार्यों की निर्माणाधीन योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 1391/प्र०अ०/बजट/बी-1 (सामान्य), दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1371/2015-II-03(55)/2015 दिनांक 17.10.2015 द्वारा स्वीकृत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट में गंगास नदी पर प्रस्तावित बैराज के निर्माण हेतु डी0पी0आर आदि कार्यों की योजना लागत रु० 110.02 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त रु० 94.02 लाख की धनराशि के व्यय के दृष्टिगत योजना की लागत अवशेष के विरुद्ध रु० 16.00 लाख (रु० सोलह लाख मात्र) की धनराशि अवशेष कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- (ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v) कार्यों के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि०-31.03.2018 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ix) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(X) विषयगत आगणन का पुनः किसी भी दशा में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2700-मुख्य सिंचाई -80-सामान्य- 005-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण-02- डी0पी0आर0 निर्माण (2700-80-800-09 से स्थानान्तरित)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3/150/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-806 (1)/ / 11-2017-03(55)/2015तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
12. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
13. मर्ज फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव